(ख) काला हिरन, घड़ियाल और नाका कस्तूरी मृग की नस्ल को लोप होने से बचाने के लिए संरक्षण देने हेतु क्या तुरन्त कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) घड़ियाल की तीन नस्लों के संरक्षण तथा प्रजनन के कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में कथरानियाघाट, उड़ीसा में भीतरकनिका तथा सतकोशिया, पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन, तमिलनाडु में सुतनूर, गुजरात में गिर, आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद तथा राजस्थान में रावत-भाटा में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) काले हिरन और घड़ियाल की नस्ल की नष्ट होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने गुजरात के वेलावदार नामक स्थान पर काले हिरन के आश्रय-स्थल के विकास के लिए गुजरात सरकार को वित्तीय सहायता दी है। भारत सरकार ने आन्ध्र, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में घड़ियाल सम्बन्धी योजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता दी है। उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में कस्तूरी-मृग फार्म की स्थापना करने के प्रस्ताव की राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करके जांच की जा रही है। नाका भारत में किसी भी स्थान पर नहीं पाया जाता।

Compulsory work by Scientists in backward areas

5490. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to depute scientists in the Agricultural Research Service, to work compulsorily in the backward areas of the country for certain period; and

(b) if so, the outlines of the proposal and objections, if any, thereto?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir. Under the rules for the Agricultural Research Service, the scientists of the Indian Council of Agricultural Research may be required to serve a minimum period of time in a backward or comparatively less developed area of the country.

(b) The question of laying down suitable guidelines for posting of scientists to those areas and of granting them compensatory benefits for working there is under consideration of the Council. No objection has been raised to the posting of scientists to such areas.

Students passed in Class X under 10+2+3 System of Education

5491. SHRI RASHID MASOOD: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) what is the total number of students who appeared at Class X examination 1977 under the new 10+2+3 pattern in Delhi;

(b) what is the total number of such students who have been detained;

(c) what is the total number of such students who have passed but having secured marks in certain subjects between 30 to 40 per cent and as such ineligible for admission in Class XI;

(d) whether certain students who have failed in Class X are being denied admission in Class X itself as regular students in their parent institution; and

(e) when the Central Board of Secondary Education has not declared any students as "Pass" or "Fail" how have they "detained" number of students?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) 47012 candidates appeared at the Delhi Secondary School Examination, 1977.

(b) and (c). As per the present criteria, students securing 30 per cent and above marks in all the subjects are eligible for admission in one or the other course to Class XI. 29594 candidates fall in this category. The students getting less than 30 per cent marks in one or two subjects are eligible for Compartmental Examination to be held on 10th August, 1977. 9669 candidates are eligible for one subject Compartment and 5765 for two subjects Compartmental Examination. These candidates on securing 30 per cent or more marks in the Compartmental Examination in one or two subjects, as the case may be, will become eligible for admission to Class XI. As such out of 47012 candidates who appeared at the 1977 Examination only 2984 candidates are not eligible for admission to Class XI.

(d) No, Sir.

(e) The candidates were not declared pass and fail but the criteria was laid down only to have a uniform policy of minimum standard for admission.

भूमि उपयोग बोर्ड

5492. **श्री मीठालाल पटेल:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को राज्यों में भूमि उपयोग बोर्डों की स्थापना करने का परामर्श दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने राज्य उक्त बोर्डों की स्थापना के लिए सहमत हो गये हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) अब तक 22 राज्य / संघ राज्य क्षेत्र भूमि उपयोग बोर्डों की स्थापना कर चुके हैं । (विवरण संलग्न है) :

इनके अलावा —

(1) गुजरात सरकार ने मृदा तथा जल प्रबन्ध निदेशालय की स्थापना की है जो उनके कथनानुसार राज्य में भूमि उपयोग बोर्ड का कार्य करेगा ।

(2) आंध्र प्रदेश की सरकार "आंध्र प्रदेश भूमि सुधार" योजना सम्बंधी विधेयक की तैयारी के प्रश्न पर विचार कर रही है, जिसमें "राज्य स्तरीय बोर्ड" की स्थापना करने की व्यवस्था है जो भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सिद्धान्तों के आधार पर भूमि उपयोग सम्बन्धी मामलों को भी निपटाएगा ।

(3) उड़ीसा और राजस्थान की सरकारें भूमि उपयोग बोर्डों की स्थापना करने के लिए सहमत हो गई हैं ।

विवरण

राज्य / संघराज्य क्षेत्र जहां भूमि उपयोग बोर्ड स्थापित किए जा चुके हैं —

1. हिमाचल प्रदेश
2. महाराष्ट्र
3. उत्तर प्रदेश
4. मध्य प्रदेश
5. हरियाणा
6. तमिलनाडु